



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1994/फाल्गुन 25, 1915

No. 121] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 1994/PHALGUNA 25, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सं. 70/94—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा.का.नि. 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 54.02 के अंतर्गत आने वाले संव्यूतित पोलिएस्टर फिलामेंट सूत को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से संगणित रकम में अधिक है, छूट देती है;

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट केवल ऐसे संव्यूतित सूत की बाबत लागू होगी :—

- (i) जो कि संव्यूतित पालिएस्टर फिलामेंट सूत के विनिर्माता के भंडार में 1 मार्च, 1994 को पड़े हुए थे, या
- (ii) जो उक्त अनुसूची के शीर्ष संख्या 54.02 के अंतर्गत आने वाले ऐसे पालिएस्टर फिलामेंट सूत (गैर-संव्यूतित) से विनिर्मित हैं जिसकी निकासी ऐसे पालिएस्टर फिलामेंट सूत (गैर संव्यूतित) के विनिर्माण के कारखाने से 1 मार्च, 1994 से पूर्व निश्चित किया गया माना गया है; या
- (iii) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष संख्या 54.02 के अंतर्गत आने वाले आयातित पालिएस्टर फिलामेंट सूत से विनिर्मित हैं जिन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन

उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का 69 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मंदाय किया है;

परन्तु यह और कि ऐसे पालिगस्टर फ़िलामेंट सूत पर संदत्त शुल्क को किसी मुजरा का केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के संयम 56 क के अधीन उपयोग नहीं किया गया है।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1994 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है तक प्रभावी होगी।

(फा. स. वी-22/1/94-टीआरयू)  
राजीव शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1994

No. 70/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts textured polyester filament yarn falling under heading No. 54.03 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1985) from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees three per kilogram :

Provided that the exemption contained in this notification shall be applicable only in respect of such textured yarn :—

- (i) which was lying in stock with the manufacturer of textured polyester filament yarn as on the 1st day of March, 1994; or
- (ii) which is manufactured out of such polyester filament yarn (non-textured) falling under heading No. 54.02 of the said Schedule as is established to have been cleared from the factory of manufacture of such polyester filament yarn (non-textured) before the 1st day of March, 1994; or
- (iii) which is manufactured out of imported polyester filament yarn (non-textured) falling under heading No. 54.02

of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) on which the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, has been paid at the rate of rupees sixty nine per kilogram :

Provided further that no credit of the duty paid on such polyester filament yarn (non-textured) has been availed of under Rule 56A of the Central Excise Rules, 1944.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1994.

[F. No. B22/1/94-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सं. 104/94—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 319 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अथवा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे आधान (कन्टेनर्स) जो टिकाऊ हों, जब उनका भारत में आयात किया जाए,

(क) उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, छूट देनी है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता ऐसे प्रत्येक में और उतनी राशि के लिए जो सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बंधपत्र निष्पादित करके अपने को आवद्ध करता है कि उपरोक्त आधानों (कन्टेनर्स) का उनके आयात में छः मास के अन्तर्गत पुनः निर्यात करेगा और उसका दस्तावेजी प्रमाण उक्त सहायक समाहर्ता, के समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत करेगा और ऐसा न कर पाने की दशा में उक्त आधानों पर उद्ग्रहणीय शुल्क का मंदाय करेगा।

परन्तु यह और कि किसी मामले विशेष में, पूर्वोक्त छः मास की अवधि, पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर, उक्त सहायक समाहर्ता द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी जो वह ठीक समझे।

[फा. सं. बी-40/1/94-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1994

NO. 104/94-CUSTOMS

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts containers which are of durable nature, falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from,

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act ;

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs binds himself to re-export the said containers within six months from the date of their importation and to furnish documentary evidence thereof to the satisfaction of the said Assistant Collector and to pay the duty leviable thereon in the event of the importer's failure to do so :

Provided further that in any particular case, the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the said Assistant Collector for such further period, as he may deem fit.

[F. No. B40/1/94-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

